+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

TODAY'S ANALYSIS
(आज का विश्लेषण)
(24 March 2025)

Sources:

The Hindu, The Indian Express, The Economics Times & PIB

Important News:

- अमेरिकी टैरिफ के मद्देनजर भारत चीन के साथ व्यापार बाधाओं को कम करने पर विचार कर रहा है
- लोकसभा की कार्य प्रक्रिया में 'गुप्त बैठक' का प्रावधान क्या होता है?
- भारत ने 10 वर्षों में, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं से आगे निकलते हुए अपने GDP को दोगुना कर दिया है: IMF डेटा
- MCQ

अमेरिकी टैरिफ के मद्देनजर भारत चीन के साथ व्यापार बाधाओं को कम करने पर विचार कर रहा है:

मामला क्या है?

- भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव कम होने के संकेत मिलने के साथ ही भारतीय नीति निर्माता अब चीन के साथ आर्थिक संबंधों को बेहतर बनाने के तरीकों पर विचार कर रहे हैं।
- उल्लेखनीय है कि भारत के इस नीति बदलाव को एक रणनीतिक कदम के रूप में देखा जा रहा है, खासकर तब जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के नेतृत्व में संयुक्त राज्य अमेरिका भारत पर टैरिफ कम करने और अमेरिका द्वारा निर्धारित व्यापार शर्तों को स्वीकार करने का दबाव बना रहा है।

व्यापार और निवेश प्रतिबंधों की समीक्षा:

- भारतीय अधिकारी 2020 में गलवान घाटी में हुई झड़पों के बाद पांच साल पहले लगाए गए कुछ व्यापार और निवेश प्रतिबंधों को कम करने या हटाने के तरीकों

की खोज कर रहे हैं। इनमें चीनी कर्मियों के लिए वीजा प्रतिबंधों में ढील देना, कुछ टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं को हटाना आदि शामिल है।

विचारणीय प्रमुख क्षेत्र:

- **वीज़ा नीतियों में ढील:** भारत सरकार चीनी श्रमिकों, विशेष रूप से बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, भारी मशीनरी की स्थापना और संबंधित कार्यों में लगे श्रमिकों के लिए वीज़ा नीतियों की समीक्षा कर रही है।
- **टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं में कमी:** चीनी वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंधों को कम करने के लिए दबाव बढ़ रहा है, खासकर उन वस्तुओं पर जो भारत में बड़े पैमाने पर उत्पादित नहीं होती हैं। वाणिज्य मंत्रालय भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के तहत कुछ गुणवत्ता प्रमाणन आवश्यकताओं को हटाने का मूल्यांकन कर रहा है जो वर्तमान में चीनी आयात को प्रभावित करती हैं।
- **निवेश नीति समायोजन:** भारत अपनी 2020 नीति में संशोधन पर विचार कर रहा है, जिसके तहत भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों से निवेश के लिए सरकार की मंजूरी अनिवार्य है। यह समायोजन चीनी कंपनियों से निवेश प्रवाह को सुविधाजनक बना सकता है, जो संभवतः चीन के साथ भारत के बढ़ते व्यापार घाटे को संबोधित करता है।

भारत के लिए यह एक रणनीतिक विचार के रूप में:

- उल्लेखनीय है कि चीन के साथ खुली आर्थिक चर्चा में शामिल होना अमेरिकी व्यापार दबावों के खिलाफ एक रणनीतिक बचाव के रूप में काम कर सकता है। वित्त मंत्रालय द्वारा हाल ही में एक प्रस्तुति में कथित तौर पर चीनी व्यापार और निवेश पर प्रतिबंधों को आंशिक रूप से हटाने के लाभों पर प्रकाश डाला गया।
- भारतीय उद्योग भी इस बदलाव के लिए दबाव बना रहा है, खासकर छोटे और मध्यम उद्यम जो चीनी इनपुट पर निर्भर हैं।

व्यापार संबंधों को मजबूत करने में चीन की रुचि:

- चीन भारत के साथ व्यापारिक संबंध बहाल करने का भी इच्छुक है। चीन के साथ भारत के बढ़ते व्यापार घाटे के मद्देनजर, चीन ने भारतीय बाजारों में चीनी निवेश बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है।
- व्यापार विशेषज्ञों का मानना है कि चीनी कंपनियों को भारतीय उद्यमों में निवेश करने की अनुमति देकर, भारत अपने स्वयं के निर्यात के लिए बेहतर बाजार पहुंच के लिए बातचीत करने में लाभ प्राप्त कर सकता है, खासकर फार्मास्यूटिकल्स और कृषि जैसे क्षेत्रों में, जो वर्तमान में चीन में महत्वपूर्ण प्रतिबंधों का सामना कर रहे हैं।

- ये वार्ताएं कुछ समय से चल रही हैं और आने वाले हफ्तों में व्यापार में छूट की घोषणा की जा सकती है। इस कदम से अमेरिका को यह संदेश भी जाएगा कि भारत के पास वैकल्पिक व्यापार साझेदार हैं।

भारत और चीन के बीच वर्तमान व्यापार परिदृश्य:

- **व्यापार मात्रा:** वित्त वर्ष 2023-24 में भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार 118.40 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। चीन ने दो साल के अंतराल के बाद अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए भारत के शीर्ष व्यापारिक साझेदार के रूप में अपना स्थान फिर से हासिल कर लिया।
- **चीन से आयात:** भारत के कुल आयात में चीन का योगदान 15% था, तथा चीन से भारत का आयात 101.74 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।
- **व्यापार घाटा:** चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा 2023 में रिकॉर्ड 83 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। यह बढ़ता असंतुलन भारत की सीमित निर्यात टोकरी, जिसमें मुख्य रूप से कच्चे माल शामिल हैं, और फार्मास्यूटिकल्स और आईटी सेवाओं जैसे भारतीय सामानों पर चीन के बाजार प्रतिबंधों के कारण है।
- **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI):** बड़े व्यापार वॉल्यूम के बावजूद, भारत में चीनी एफडीआई अपेक्षाकृत कम है। अप्रैल 2000 से सितंबर 2024 के बीच, चीन ने

एफडीआई में केवल 2.5 बिलियन डॉलर का योगदान दिया, जिससे वह भारत के विदेशी निवेशकों की सूची में 22वें स्थान पर आ गया।

भारत-चीन व्यापार को लेकर चुनौतियां:

- प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा हाल ही में जारी किए गए एक कार्य पत्र में बताया गया है कि भारतीय निर्यातकों को चीन में कई गैर-टैरिफ बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। इन मुद्दों को संबोधित करने से भारत की बाजार पहुंच में सुधार हो सकता है और व्यापार संबंधों में संतुलन हो सकता है।
- इस बीच, चीन आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा है, जिसमें घरेलू आवास संकट और 'चीन प्लस वन' नीति के तहत पश्चिमी निवेश रणनीतियों में बदलाव शामिल है। जबकि भारत ने खुद को एक वैकल्पिक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित किया है, चीन से पूरी तरह से आर्थिक अलगाव मुश्किल बना हुआ है।
- ऐसे में चीनी निवेश के लिए धीरे-धीरे द्वार खोले जा सकते हैं, मुख्य रूप से संयुक्त उद्यमों के माध्यम से, जहां भारतीय कंपनियों का बहुमत नियंत्रण बना रहेगा।
- भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में चीनी निवेश को प्रोत्साहित करने की सिफारिश की गई है, जबकि न्यूनतम स्थानीय मूल्य संवर्धन वाले तैयार माल के आयात को हतोत्साहित किया जाना चाहिए।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

आगे की राह:

- उल्लेखनीय है कि भारत और चीन के बीच तनाव कम हो गया है, लेकिन दोनों देश सावधानीपूर्वक आर्थिक रूप से फिर से जुड़ने के तरीके तलाश रहे हैं।
- भारत की रणनीति चीन के प्रति व्यावहारिक दृष्टिकोण के साथ अमेरिकी व्यापार दबावों को संतुलित करने की प्रतीत होती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी नीतिगत बदलाव आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देते हुए राष्ट्रीय हितों की रक्षा करे।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

लोकसभा की कार्य प्रक्रिया में 'गुप्त बैठक' का प्रावधान क्या होता है?

परिचय:

- संसद के निचले सदन लोकसभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण संसद टीवी पर किया जाता है। लेकिन भारत के संविधान में आवश्यकता पड़ने पर लोकसभा की 'गुप्त बैठक' आयोजित करने का प्रावधान किया गया है। सदन के नेता के अनुरोध पर गुप्त बैठक आयोजित करने का प्रावधान है।
- उल्लेखनीय है कि लोकसभा में 'गुप्त बैठक' का प्रावधान सरकार को संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा करने की अनुमति देता है। हालांकि, इस प्रावधान का अभी तक उपयोग नहीं किया गया है।

लोकसभा में 'गुप्त बैठक' का प्रावधान क्या है?

- उल्लेखनीय है कि लोकसभा की गुप्त बैठक से संबंधित प्रावधान लोकसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के अध्याय XXV के नियम 248-252 में दिए गए हैं।

- नियम 248 के उपखण्ड एक के अनुसार, सदन के नेता के अनुरोध पर अध्यक्ष सदन की गुप्त बैठक के लिए एक दिन या उसका एक भाग निश्चित करेंगे। जब सदन गुप्त रूप से बैठेगा तो किसी भी अजनबी को चैंबर, लॉबी या गैलरी में उपस्थित होने की अनुमति नहीं होगी। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें ऐसी बैठकों के दौरान अनुमति दी जाएगी।
- गुप्त सत्र के दौरान सदन के सदस्यों या किसी अन्य व्यक्ति की उपस्थिति की अनुमति तभी दी जाती है जब उसे सदन के अध्यक्ष द्वारा विधिवत अधिकृत किया जाता है।
- ध्यातव्य है कि संसद और विधानमंडल की गुप्त बैठकें आयोजित करने की प्रथा भारत द्वारा ब्रिटेन से अपनाई गई अवधारणा है। ब्रिटिश संसद ने वर्ष 1916 में हाउस ऑफ कॉमन्स की गुप्त बैठक की शुरुआत की थी।

क्या भारत ने कभी लोकसभा की गुप्त बैठक आयोजित की है?

- उल्लेखनीय है कि सरकार को संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा करने के लिए लोकसभा की "गुप्त बैठक" बुलाने की अनुमति देने वाले नियमों का अब तक उपयोग नहीं किया गया है।

- हालांकि, भारत ने लोकसभा की "गुप्त बैठक" आयोजित करने के सबसे करीब 1962 में सीमा पर चीनी आक्रमण के दौरान आया था, जब विपक्षी सांसदों में से कुछ ने सदन की गुप्त बैठक बुलाकर इस मामले पर चर्चा करने का विचार रखा। लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने यह कहते हुए इनकार कर दिया था कि जनता को सदन की कार्यवाही पता होनी चाहिए।
- संवैधानिक विशेषज्ञ और लोकसभा के पूर्व महासचिव पीडीटी अचारी ने कहा कि सदन की गुप्त बैठक बुलाने का "कोई अवसर" नहीं आया है। उन्होंने कहा कि 1962 में चीन-भारत संघर्ष के दौरान कुछ विपक्षी सदस्यों ने संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा के लिए गुप्त बैठक का प्रस्ताव रखा था।

कोई भी कार्यवाही का ब्यौरा नहीं रख सकता:

- लोकसभा की गुप्त बैठक के नियमों में से एक यह है कि अध्यक्ष यह निर्देश दे सकता है कि गुप्त बैठक की कार्यवाही की रिपोर्ट उस तरीके से जारी की जाए जैसा अध्यक्ष उचित समझे।
- नियमों में कहा गया है, "लेकिन कोई भी अन्य उपस्थित व्यक्ति गुप्त बैठक की किसी भी कार्यवाही या निर्णय का नोट या रिकॉर्ड नहीं रखेगा, चाहे वह आंशिक हो

या पूर्ण, या ऐसी कार्यवाही की कोई रिपोर्ट जारी नहीं करेगा या उसका वर्णन करने का दावा नहीं करेगा"।

- उल्लेखनीय है कि नियमों में यह भी कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी तरीके से गुप्त कार्यवाही या बैठक की कार्यवाही या निर्णयों का खुलासा करना "सदन के विशेषाधिकार का घोर उल्लंघन" माना जाएगा।

क्या कार्यवाही के विवरण कभी उजागर हो सकते हैं?

- जब यह माना जाता है कि किसी गुप्त बैठक की कार्यवाही के संबंध में गोपनीयता बनाए रखने की आवश्यकता नहीं रह गई है, तब अध्यक्ष की सहमति से सदन का नेता या कोई अधिकृत सदस्य प्रस्ताव पेश कर सकता है कि ऐसी बैठक के दौरान की कार्यवाही को अब गुप्त नहीं माना जाए।
- यदि प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो महासचिव "गुप्त बैठक" के दौरान कार्यवाही की एक रिपोर्ट तैयार करेंगे और इसे जल्द से जल्द प्रकाशित करेंगे।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

भारत ने 10 वर्षों में, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं से आगे निकलते हुए अपने GDP को दोगुना कर दिया है: IMF डेटा

भारत की उल्लेखनीय दशकीय वृद्धि दर:

- IMF के आंकड़ों के अनुसार, भारत ने अपने सकल घरेलू उत्पाद (GDP) को 2015 में 2.1 ट्रिलियन डॉलर से दोगुना करके 2025 में 4.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाकर एक महत्वपूर्ण आर्थिक उपलब्धि हासिल की है, जो 105% की दशकीय वृद्धि को दर्शाता है - जो प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में एक अभूतपूर्व वृद्धि दर है। इसकी तुलना में, इसी अवधि के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के GDP में क्रमशः 66 प्रतिशत और 44 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
- इसके साथ ही, भारत अब संयुक्त राज्य अमेरिका ($30.3 ट्रिलियन), चीन ($19.5 ट्रिलियन), जर्मनी ($4.9 ट्रिलियन) और जापान ($4.4 ट्रिलियन) के बाद GDP के मामले में दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा देश है। वहीं IMF के आंकड़ों के अनुसार,

भारत 2025 में जापान से आगे निकल जाएगा और संभवतः 2027 तक जर्मनी से आगे निकल जाएगा।

विश्व के अन्य देशों का प्रदर्शन:

- **चीन का प्रदर्शन:** इस बीच, चीन ने इसी अवधि में 74 प्रतिशत की प्रभावशाली GDP वृद्धि दर्ज की, जो 2015 में 11.2 ट्रिलियन डॉलर से बढ़कर 2025 में 19.5 ट्रिलियन डॉलर हो गई। हालांकि, पहले के अनुमान कि चीन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका से आगे निकल जाएगा, महामारी और चल रही संपत्ति क्षेत्र की चुनौतियों से उत्पन्न आर्थिक प्रतिकूलताओं के कारण साकार नहीं हुआ है।
- **संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रदर्शन:** वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका ने दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखी, इसकी GDP 2015 में 23.7 ट्रिलियन डॉलर से बढ़कर 2025 में 30.3 ट्रिलियन डॉलर हो गई, जो 28 प्रतिशत की

वृद्धि दर दर्शाती है। एशियाई अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में धीमी होने के बावजूद, वैश्विक आर्थिक स्थिरता में अमेरिका एक प्रमुख शक्ति बना हुआ है।

- **यूके., फ्रांस, जर्मनी और जापान सहित अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं** ने दशक भर में 6% से 14% तक की मध्यम GDP वृद्धि दर्ज की। अपने अपेक्षाकृत धीमे विस्तार के बावजूद, ये राष्ट्र वैश्विक व्यापार और वित्त में महत्वपूर्ण प्रभाव बनाए रखते हैं।

ब्राजील का शीर्ष 10 देशों में सबसे ख़राब प्रदर्शन:

- ब्राजील ने शीर्ष दस अर्थव्यवस्थाओं में सबसे कम GDP वृद्धि दर्ज की, जो 2015 में $2.1 ट्रिलियन से 2025 में $2.3 ट्रिलियन तक केवल 8 प्रतिशत की वृद्धि के साथ है।
- 2014 के कमोडिटी क्रैश ने देश के आर्थिक संघर्षों को और बढ़ा दिया, जिससे लंबे समय तक मंदी रही, जो COVID-19 महामारी के कारण होने वाले व्यवधानों से और भी जटिल हो गई।

MCQs

1. चर्चा में रहे 'वित्त वर्ष 2023-24 में भारत और चीन के बीच वर्तमान व्यापार परिदृश्य' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

   1. इस वित्तीय वर्ष में चीन भारत का दूसरे सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार रहा है।
   2. भारत के कुल आयात में चीन का योगदान सर्वाधिक रहा, जो कुल आयात का 15% रहा है।

   उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

   (a) केवल 1

   (b) केवल 2

   (c) 1 और 2 दोनों

   (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

   Ans:(b)

2. चर्चा में रहे लोकसभा की 'गुप्त बैठकों' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

   (a) भारत के संविधान में आवश्यकता पड़ने पर लोकसभा की 'गुप्त बैठक' आयोजित करने का प्रावधान किया गया है।

(b) संसद की गुप्त बैठकें आयोजित करने की प्रथा भारत द्वारा जर्मनी से अपनाई गई अवधारणा है।

(c) भारत में लोकसभा की "गुप्त बैठक" का आयोजन केवल एक बार 1962 में सीमा पर चीनी आक्रमण के दौरान किया गया था।

(d) उपर्युक्त सभी सही कथन हैं।

Ans:(a)

3. चर्चा में रहे 'भारत-चीन व्यापार से जुड़े चुनातियों एवं अवसर' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. भारतीय निर्यातकों को चीन में कई गैर-टैरिफ बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है।
2. आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में चीनी निवेश को प्रोत्साहित करने की सिफारिश की गई है।

उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं।

Ans:(c)

4. लोकसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के तहत लोकसभा की गुप्त बैठक का आयोजन किया जा सकता है। इस बैठक का आयोजन लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किस के अनुरोध पर किया जाता है?

(a) राष्ट्रपति के के प्रस्ताव पर

(b) सदन के बहुमत के प्रस्ताव पर

(c) नेता प्रतिपक्ष के प्रस्ताव पर

(d) नेता सदन के प्रस्ताव पर

Ans:(d)

5. चर्चा में रहे भारत के सकल घरेलू उत्पाद को लेकर IMF के आंकड़ों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. भारत का सकल घरेलू उत्पाद 2015 के 2.1 ट्रिलियन डॉलर से दोगुना होकर 2025 में 4.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया है।
2. भारत का सकल घरेलू उत्पाद का 2025 में जर्मनी से और 2027 तक जापान से आगे निकलने की संभावना है।

उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं।

Ans:(a)